'अगले वर्ष हर श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी की जायेगी'

गौशालाओं की अनुदान राशि के लिये गौपालकों व संतों ने मुख्यमंत्री भजनलाल का आभर प्रकट किया

जयपुर, 10 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हाल में पेश किए गए राज्य के बजट में गौमाता और पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेशभर में संचालित गौशालाओं तथा नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को इस वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रूपये प्रतिदिन करने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर आयोजित आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की थी, जिसमें गौवंश हेतु शैड, खेली निर्माण तथा दुग्ध, चारा, बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए एक लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हम आगामी वित्त वर्ष में भी ढाई लाख गोपालक परिवारों को इस योजना का लाभ मुहैया कराएंगे। शर्मा ने कहा कि गोपालकों को और अधिक राहत देते हुए, गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी माफ करने और योजना के प्रावधानों को सरल बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान का प्रवासी भी देश-दुनिया में अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है तथा प्रवासियों ने हर जगह गौशालाएं बनायी हैं, जिससे गौसेवा के पुण्य कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' के दायरे को बढ़ाते हुए, आगामी वित्त वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी की जाएगी।

आभार सभा में आए संतों ने मुख्यमंत्री द्वारा गौ-संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यो के लिए आभार जताया।

भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर आयोजित आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा में आए संतों के साथ फूलों की होली खेली, चंग बजाकर होली के गीत गाए तथा सभी को होली की बधाइयां दीं।

- **आभार सभा से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल ने गौ-पूजा की तथा संत-महंतों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने सभी के साथ फूलों की होली खेली व चंग बजाकर होली के गीत गाये।**
- **मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल शुरु की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में अगले वर्ष ढाई लाख गौपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।**

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ने गौसेवा का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। गत सरकार में गौ भक्तों को गौ-संरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन इस सरकार में हमारे लिए आशीर्वाद कार्यक्रम हो रहे हैं।

कार्यक्रम से पूर्व, मुख्यमंत्री ने गौ-पूजा की तथा संत-महन्तों से आशीर्वाद लिया। संतों ने मुख्यमंत्री को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने उल्लासपूर्वक सभी के साथ फूलों की होली खेली, चंग बजाकर होली के गीत गाए तथा सभी को होली की बधाइयां दीं।

न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री 16 को भारत आयेंगे

नयी दिल्ली, 10 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16-20 मार्च के दौरान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यहां बताया कि लक्सन के साथ, उनकी सरकार के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यवसायियों, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों सहित न्यूजीलैंड का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा।

प्रधानमंत्री के रूप में लक्सन की यह पहली भारत यात्रा होगी। वे 20 मार्च को वेलिंगटन लौटने से पहले मुंबई भी जाएंगे। लक्सन 17 मार्च को मोदी के साथ भारत-न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मोदी गणमान्य अतिथि के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी करेंगे। वे उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी भेंट करेंगे।

- **वे 17 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे।**

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 17 मार्च को अपराह्न नई दिल्ली में 10वीं रायसीना संवाद 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देंगे। वे 19-20 मार्च को मुंबई में रहेंगे, जहां वे भारतीय व्यापारिक नेताओं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि लक्सन की यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। यह सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा हमारे लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को गहरा करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त

- **न्यायमूर्ति बागची 2011 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे तथा अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में नियुक्त थे।**
- **वे 2 अक्टूबर 2031 को सेवानिवृत्त होंगे तथा मई 2031 में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।**

नयी दिल्ली, 10 मार्च। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बागची की पदोन्नित संबंधी घोषणा की। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर उनकी इस पदोन्नित की घोषणा से संबंधित जानकारी साझा की है।

न्यायमूर्ति बागची के शपथ ग्रहण के साथ ही, शीर्ष अदालत के लिए स्वीकृत 34 न्यायाधीशों की संख्या के मुकाबले न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी। न्यायमूर्ति बागची दो अक्टूबर 2031 को सेवानिवृत्त होंगे, उससे पहले वे मई (2031) में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।

शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले न्यायमूर्ति भूषण आर गवई, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के कॉलेजियम ने छह मार्च को न्यायमूर्ति बागची को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशपद पर नियुक्ति की सिफारिश की थी।

न्यायमूर्ति बागची को बतौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कानून के विविध क्षेत्रों में 13 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त है। उन्हें जून 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जनवरी 2021 में उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया और फिर नवंबर 2021 में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया।

'1247 शराब की दुकानों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गुटबाजी (कटिलाइजेशन) को रोका जा सके। उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में कई व्यवसायी मिलकर शराब की दुकानों के 'क्लस्टर' में कुछ दुकानों को खरीदते नहीं थे, जिससे पूरे 'क्लस्टर' की दरें गिर जाती थी, और राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती थी। उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ दुकानें, जो नहीं बिकी होती थीं, उन दुकानों से गैरकानूनी तरीके से शराब बेची जाती थी, और राज्य सरकार को राजस्व में और भी हानि होती थी। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई नीति में 70 प्रतिशत "रिन्यूअल" की शर्त लगाई है। उन्होंने अदालत को बताया कि नई नीति के अनुसार, किसी भी जिले में अगर 70 प्रतिशत शराब की दुकानें नीलामी में पुराने व्यवसायियों ने ही खरीदी हो, तो इनको बची हुई दुकानें खरीदने का विकल्प दिया जाता है, ताकि ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो कि कुछ दुकानें अनबिकी रह जाएं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 11 मार्च को होने वाली दुकानों की नीलामी पर रोक से इनकार दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता भी नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं।

कोचिंग सैन्टर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण और विद्यार्थियों को संबल व सुरक्षा देने के उद्देश्य से दी राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल, 2025 गत दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया है। इस बिल को कानूनी मान्यता देने के लिए, इसे इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसे में मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाली जाए। इस पर अदालत ने मामले में की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है। गौरतलब है कि विद्यार्थियों को संबल और सुरक्षा देने के लिए बनाए गए इस बिल में विद्यार्थियों के लिए कई कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं। वहीं, कोचिंग सेंटरों पर पर नियंत्रण करने के लिए कई बिंदु शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, विद्यार्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। दरअसल, कोचिंग सेंटरों के विद्यार्थियों द्वारा आए दिन आत्महत्या करने की घटनाओं को देखते हुए, हाईकोर्ट ने साल 2016 में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरु की थी।

वानुआतू प्रधानमंत्री ने ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द किया

- **प्रधानमंत्री जोथम नापत ने कहा कि वानुआतू का पासपोर्ट एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार। आवेदकों को नागरिकता के लिए वैध कारण दिखाने चाहिये।**
- **प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने नागरिकता आयोग को मोदी के वातुआतू पासपोर्ट को रद्द करने की कार्यवाही तुरंत शुरु करने का निर्देश दिया है।**

नई दिल्ली, 10 मार्च। वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को पूर्व आईपीएल प्रमुख और भगोड़े ललित मोदी को जारी वानुआतू पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया है। रिपोर्टों और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक कथित प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नापत ने कहा कि हालांकि जांच में कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में उन्हें बताया गया कि इंटरपोल ने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण ललित मोदी पर अलर्ट जारी करने के भारतीय अनुरोधों को दो बार अस्वीकार कर दिया है।

प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है, मैंने नागरिकता आयोग को मोदी के वानुआतु पासपोर्ट को रद्द करने की कार्यवाही तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। इस तरह की कोई भी चेतावनी ललित मोदी के नागरिकता आवेदन को स्वत: ही अस्वीकार कर दिया है।

उन्होंने कहा है कि वानुआतू का पासपोर्ट एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार, और आवेदकों को वैध कारणों से नागरिकता दिखानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में उनकी सरकार ने निवेश कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश की नागरिकता के लिए उचित प्रक्रिया को मजबूत किया है। बयान में कहा गया है कि अद्यतन प्रक्रिया में इंटरपोल सत्यापन सहित ट्रिपल-एजेंसी जांच शामिल है।

वानुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है। इसमें 83 द्वीपों का एक द्वीपसमूह शामिल है, जिनमें से 65 पर लोग रहते हैं।

हाई कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आदेश दिया गया था, वह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत, त्रुटिपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ थी। ऐसे में 25 फरवरी के आदेश के रिव्यु या उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए समय दिया जाए और इस दौरान इस खंडपीठ की ओर से गत 7 मार्च को दिए गए यथास्थिति के आदेश को जारी रखा जाए। इस पर अदालत ने कहा कि 25 फरवरी को दिया गया आदेश खंडपीठ का था और यह भी उसके समान ही खंडपीठ है। इसलिए वह उस आदेश के खिलाफ आदेश नहीं दे सकती। गौरतलब है कि मामले में प्रसंज्ञान लेने के बाद, नगर निगम ने परकोटे के भवनों को लेकर तीन तरह की सूची बनाई थी। पहली सूची में उन 19 इमारतों को शामिल किया गया था, जो पूरी तरह अवैध हैं। हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ ने गत 25 फरवरी को इन इमारतों को सील करने के आदेश दिए थे। वहीं, इस खंडपीठ ने गत 7 फरवरी को मामले में अंतरिम रूप से यथा-स्थिति के आदेश दिए थे।

बंधकों की रिहाई के लिये इज़रायल ने गाज़ा की बिजली बंद की

- **इज़रायल के अनुसार, अब भी 59 बंधक हमास की कैद में हैं, जिनमें से 24 के जीवित होने का अनुमान है।**

यरूशलम, 10 मार्च। इज़रायल ने रविवार को घोषणा की कि वह हमास पर बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव डालने के लिए गाज़ा पट्टी की बिजली आपूर्ति बंद कर रहा है। इज़रायली ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने एक वीडियो बयान में कहा, मैंने अभी-अभी गाज़ा को बिजली की आपूर्ति तुरंत रोकने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य हमास पर उन लोगों को रिहा करने का दबाव बनाना है, जो अब भी गाज़ा में बंधक हैं।

इज़रायली आंकड़ों के अनुसार, अब भी 59 बंधक हमास की कैद में हैं, जिनमें से लगभग 24 के जीवित होने का अनुमान है। कोहेन ने कहा, हम सभी बंधकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेंगे और गारंटी देंगे कि हमास (युद्ध) के अगले दिन गाज़ा में नहीं रहेगा।

ऊर्जा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से जारी किये गये एक पत्र में देश के स्वामित्व वाली इज़रायल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को गाज़ा को बिजली की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया। उनके प्रवक्ता ने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा।

गौरतलब है कि इज़रायल ने दो मार्च को इजरायल-हमास युद्ध विराम का पहला 42-दिवसीय चरण समाप्त होने के साथ ही गाज़ा में खाद्य सामग्री सहित सहायता शिपमेंट को रोक दिया है।

हमास के अधिकारी तीन-चरण वाले युद्ध विराम के कार्यान्वयन पर नजर के लिए मिस्र और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमास ने गाज़ा पट्टी में बिजली आपूर्ति बंद करने के इज़रायल के फैसले को 'सस्ता ब्लैकमेल' और गाज़ा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते का 'स्पष्ट उल्लंघन' करार दिया है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल-रिशेक ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा, बिजली आपूर्ति में कटौती, क्रॉसिंग बंद करना, सहायता, राहत और ईंधन के प्रवेश को रोकना और हमारे लोगों को भूखा रखना सामूहिक दंड देने का प्रयास है, जो एक पूर्ण अपराध है।

बिहारः तनिष्क शोरुम में 25 करोड़ रूपए की लूट

आरा (भोजपुर), 10 मार्च। बिहार में आरा के गोपाली चौक स्थित तनिष्क शोरूम से सोमवार को 6 बदमाश 25 करोड़ की ज्वेलरी लूट ले गए। बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस ने फायरिंग की। दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उनके पास से दो झोला ज्वेलरी बरामद की गई। 4 बदमाश बाकी ज्वेलरी लेकर भाग गए। शोरूम के स्टोर मैनेजर कुमार मृत्युंजय ने बताया, शोरूम में 50 करोड़ से ज्यादा के जेवरात थे। अपराधियों ने 25 करोड़ के गहने लूट लिए।

सोमवार सुबह साढ़े 10 बजे 3 बाइक से आए 6 बदमाशों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट कर उसका हथियार भी छीन लिया।

शोरूम में घुसते ही शटर अंदर से बंद करके करीब 22 मिनट तक दोनों फ्लोर पर लूटपाट की। भोजपुर के राज ने बताया, पुलिस ने शोरूम के अंदर लूट की फोटो वॉट्सऐप ग्रुप में शेयर की थी। बड़हरा थाना पुलिस ने बबुरा छोटे पुल के पास 3 बाइक पर 6 संदिग्धों को देखा। उनके रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उनके पास से 2 पिस्टल, 10 कारतूस, 2 बड़े झोले में तनिष्क शोरूम से लूटे गए जेवरात मिले हैं। इनके नाम सारण जिले के दिघवारा निवासी विशाल गुप्ता और सोनपुर के सेमरा निवासी कुणाल कुमार हैं।

जेईएन भर्ती पेपर ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर्याप्त सबूतों का अभाव है। मामले में पेश चार आरोप पत्रों में भी उसका नाम नहीं है। इसके अलावा, सह आरोपियों के बयान के अतिरिक्त याचिकाकर्ता से ऐसी कोई सामग्री बरामद नहीं हुई, जिससे यह साबित हो सके कि वह जेईएन परीक्षा का पेपर लीक करने और उसे वितरित करने में सीधे तौर पर शामिल था। ऐसे में सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड याचिकाकर्ता की जमानत को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा ने अदालत को बताया कि मामले में साल 2020 में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसे 29 फरवरी, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इन चार सालों में जांच जारी रही और कई लोगों के खिलाफ कुल पांच आरोप पत्र पेश हुए। ये सभी आरोप पत्र उसकी गिरफ्तारी से पूर्व पेश हुए थे और इनमें जांच लंबित रखने वाले आरोपियों की सूची में भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। याचिकाकर्ता की भूमिका को लेकर जांच एजेंसी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है। याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ पेश आरोप पत्र में दर्जनों गवाह हैं। इसलिए मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य सह आरोपियों से मिला हुआ है। आरोपी ने परीक्षा से पूर्व पेपर को परीक्षार्थियों तक पहुंचाया। इसके अलावा याचिकाकर्ता का पेपर लीक के मामलों का लंबा इतिहास रहा है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

बम की धमकी के कारण एयर इण्डिया का विमान वापस लौटा

मुंबई, 10 मार्च। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले एयर इंडिया के विमान (एआई119) को सोमवार को बम की धमकी के बाद बीच उड़ान से ही वापस लौटना पड़ा।

एयर इंडिया के बयान के अनुसार, उड़ान भरने के आठ घंटे बाद विमान के शौचालय में विस्फोट की धमकी भरा नोट मिला। बोइंग 777 विमान, जिसमें 303 यात्री और 19 चालक दल के सदस्य सवार थे, अजरबैजान के ऊपर से उड़ रहा था। उसी दौरान, विमान ने अपना रास्ता बदला और मुंबई लौट आया। लैंडिंग के बाद, विमान की जांच की गई, लेकिन बाद में पता चला कि धमकी भरा अलर्ट झूठ था।

मुंबई पुलिस के जोन-8 के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि की और कहा कि यह शौचालय में पाया गया एक सामान्य धमकी भरा नोट है। प्रक्रिया के अनुसार आगे की जांच जारी है।

एयरलाइन के अनुसार, अब विमान 11 मार्च को सुबह पांच बजे उड़ान भरेगा।

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि संभावित सुरक्षा खतरे के बाद मुंबई लौटने का फैसला लिया गया। बयान के मुताबिक, यात्रियों को आवास, भोजन और अन्य सहायता प्रदान की गई है।

पंजाब में किसानों ने मंत्रियों व विधायकों के घरों का घेराव किया

- **किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक अधूरी छोड़ने की आलोचना की।**
- **किसानों ने कहा, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की आवाज़ दबा रही है।**

चंडीगढ़, 10 मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की अगुवाई में किसान आज पंजाब के सभी मंत्रियों व आप विधायकों के घरों का घेराव किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आ ान पर विभिन्न जत्थेबंदियों ने भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के नेतृत्व में सुनाम में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, दिडबा में वित्त मंत्री हरपाल चीमा, लहरागागा में कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल के घरों के बाहर धरने दिए।

किसान नेताओं ने सरकार पर किसानों की आवाज दबाने के आरोप लगाए । किसानों की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 5 मार्च को चंडीगढ़ में आंदोलन किया जाना था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने 4 मार्च को ही किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और 5 मार्च को जब किसानों ने चण्डीगढ़ की ओर कूच किया तो पुलिस ने छापे मारकर और दीवारें लांघकर कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया।

सुनाम में धरने को संबोधित करते जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि संघर्षों को डंडे और सत्ता के जोर से कभी नहीं दबाया जा सकता। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा । मुख्यमंत्री अपनी बचकानी आदतों का त्याग करें अन्यथा लोग के पास बड़ी शक्ति है। इस मौक़े पर बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, युवा और माताएं मौजूद थीं।

संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर किसानों ने सोमवार को मुक्तसर जिले के तीन विधायकों की कोठियों का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक बीच में अधूरी छोड़ दी थी। ये बैठक बेनतीजा रहने से किसानों में रोष है।

टैंकर-जीप...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुंडन संस्कार कराने मैहर के झोखो जा रहे थे। उनके परिवार के साथ ससुराल पक्ष के लोग भी थे। टैंकर सीधी से बहरी की ओर जा रहा था। रात करीब ढाई बजे उपनी पेट्रोल पंप के पास दोनों वाहनों में आमने-सामने से टक्कर हो गई।

कांग्रेस की अटपटी स्थिति हो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विरोध करते है। मर्जी हो तो हम हिंदी सीखते हैं, जैसे मैंने सीखी है। हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हो सकती है। पर, यह राष्ट्रभाषा नहीं है। उन्होंने कहा, हिंदी के बाद तेलुगू है, जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो केन्द्र सरकार उसे प्रमोट क्यों नहीं करती है।

कर्नाटक सरकार ने भी त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध किया है और दोभाषा फॉर्मूला का समर्थन किया है। कर्नाटक में कुछेक घटनाएं हुईं, जहाँ हिंदी बोलने वाले उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हुईं थीं।

भाषा मुद्दे पर तमिलनाडु और केन्द्र सरकार कोई भी एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु का तर्क है कि हिंदी के बिना भी राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है तो वह हिंदी भाषा क्यों पढ़े। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पी. त्यागराजन ने कहा कि हिंदी बैल्ट के कितने छात्र है, जो दो भाषाओं में माहिर है। पहले दो भाषाएं सीखिए, फिर हम तीन भाषाओं की बात करेंगे। उन्होंने कहा, उत्तर भारत के अधिकांश विद्यार्थी एक भाषा में भी पारंगत नहीं है कि वे उसे सही तरीके से लिख-पढ़ सके।

सोमवार को भाषा मुद्दा संसद पहुँच गया। द्रमुक सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर सीधा हमला बोला, क्योंकि उन्होंने केन्द्र व राज्य के बीच केन्द्र द्वारा तमिलनाडु के भाषा के गतिरोध पर बोलते हुए असभ्य व अलोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया था। उनके शब्दों से द्रमुक सांसद भड़क गए। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर तमिलों का अपमान करने का आरोप लगाया।

स्टालिन ने भी मंत्री पर अक्खड़ व्यवहार का आरोप लगाया। लोकसभा में द्रमुक की नेता कनिमोई ने कहा कि वे इस बात से बेहद आहत और दुखी हैं कि शिक्षा मंत्री ने तमिल सांसदों, तमिल सरकार और तमिल लोगों को असभ्य कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमारी मीटिंग में मुख्यमंत्री स्टालिन ने साफ कह दिया था कि त्रिभाषा फॉर्मूला स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिखा और फंड जारी करने का आग्रह किया। स्टालिन ने अपने बयान में कहा कि "क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तमिलनाडु की जनता का अपमान स्वीकार्य है।"

पत्रकारों से बात करते हुए कनिमोई ने कहा, मंत्री "फेक" न्यूज़ से ध्यान भटका रहे हैं, उनके अपमानजनक भाषण की निंदा की जानी चाहिए।

तिरूवल्लूर के सांसद शशिकांत सैंथिल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनके शब्दों से उनकी सर्वोच्चतावादी मानसिकता झलकती है। यह स्पष्ट है कि इसी मानसिकता से केन्द्र सरकार तमिलनाडु पर राज करती है।

राहुल गाँधी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूची में डुप्लीकेट नामों का नया साक्ष्य सामने आ गया है, जो और भी ज्यादा गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है।" लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र तथा संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिये यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। ईपीआईसी में डुप्लीकेशन को लेकर कांग्रेस सहित, विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना के परिणामस्वरूप, ईसीआई ने कहा है कि "लम्बे समय से लम्बित" इस मुद्दे का समाधान अगले तीन महीनों में हो जायेगा।

अहमदाबाद-मुम्बई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जापान और भारत ने अभी तक एमएएचएसआर कॉरिडोर पर लगने वाले सिग्नलिंग सिस्टम्स से संबंधित एग्रीमेंट पर भी विचार-विमर्श नहीं किया है। जापान "लीकी केबल" सिस्टम्स पर अड़ा हुआ है, जो शिंकनसेन ट्रेनों में परम्परागत रूप से से काम में लिये जाते थे, जबकि भारत सरकार ईसीटीएस-2 सिस्टम्स को काम में लेने पर विचार कर रही है, जो दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांज़िट सर्विस (आरआरटीएस) लाइन, जो पूर्ण होने को है, में काम में लिये जा रहे हैं।

ट्रम्प के मनमर्ज़ी वाले निर्णय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के नेतृत्व में एक स्वतंत्र नीति मार्ग अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन, अब कुछ बदलावों की आशंका जताई जा रही है।

कैनडा की लिबरल पार्टी के नेता चुने गए कार्नी, पहले बैंक ऑफ कैनडा के गवर्नर थे तथा उसके बाद बैंक ऑफ इंगलैण्ड के एक उच्च प्रोफाइल व अंतर्राष्ट्रीय रूप से सम्मानित गवर्नर थे।

पार्टी का नेता चुने जाने के तुरंत, बाद कार्नी ने यू. एस. टैरिफ वॉर और आर्थिक हमलों से लड़ने की अपनी बुनियादी रणनीति निर्धारित की। कार्नी ने ट्रम्प टैरिफ के जवाब में सख्त कदम उठाने का वादा किया है।

वे कैनडा के लोगों की वर्तमान अमेरिका विरोधी भावनाओं का लाभ उठाते हुए, अर्थव्यवस्था पर लड़ाई लड़ने के लिए कई उपायों को लागू करने का वादा कर रहे हैं। नेता चुने जाने के बाद अपने भाषण में कार्नी ने समूची लड़ाई को, यह कहते हुए, पूरी तरह से आर्थिक रूप दिया कि ट्रम्प कैनडा के साधारण परिवारों की आजीविका को लक्ष्य बना रहे हैं।

इसका मतलब है कि कैनडा, अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगा सकता है, ताकि इन वस्तुओं के देश में और अधिक प्रवाह को रोका जा सके। अमेरिका को सप्लाई किए जाने वाले एनर्जी उत्पादों पर कैनडा का नियंत्रण है। कैनडा, अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले ऊर्जा उत्पादों का एक प्रमुख एक्सपोर्टर है।

तथापि, कार्नी को अमेरिका के खिलाफ अपनी क्रूसेड शुरू करने से पहले अपनी घरेलू लड़ाई को प्रभावी ढंग से लड़ना होगा। ट्रूडो के नेतृत्व में, सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने चुनावी आधार खो दिया था और कन्ज़र्वेटिव पार्टी ने धीरे-धीरे अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था।

कन्ज़र्वेटिव पॉलिटीशियन, पियर पॉलिएव ने सत्तारूढ़ पार्टी पर यू. एस. के हमलों का सामना करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था। ट्रूडो के समय विपक्षी पार्टी की स्थिति सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी से बेहतर हो गई थी।

तथापि, मार्क कार्नी के नए नेता बनने के बाद कंज़र्वेटिव पार्टी एक नए संघर्ष की उम्मीद कर रही है। कार्नी के ये बयान, कि वे अमेरिका से हार नहीं मानेंगे, देश भर में बहुत सराहे गए हैं और पोल्स में लिबरल पार्टी अब वापस कन्ज़र्वेटिव्ज़ के नज़दीक आ रही है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908